



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 321 राँची, शनिवार, 30 वैशाख, 1938 (श०)
20 मई, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

17 फरवरी, 2017

कृपया पढ़ें:-

1. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार का संकल्प संख्या- 9910, दिनांक 13 सितम्बर, 1996
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प सं०-5898, दिनांक 7 नवम्बर, 2008, संकल्प संख्या-1111, दिनांक 8 फरवरी, 2016, पत्रांक-1316, दिनांक 15 फरवरी, 2016 एवं पत्रांक-7773, दिनांक 7 सितम्बर, 2016
3. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-238, दिनांक 25 जनवरी, 2017

संख्या-5/आरोप-1-697/2014 का.-1492-- श्री सुरेश मिश्र, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-267/03, गृह जिला- हजारीबाग), के विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी सं०-1 स्वर्णरेखा परियोजना मानगो, जमशेदपुर के पद पर कार्यावधि से संबंधित आरोप प्रपत्र- 'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आरोप है कि

श्री मिश्र द्वारा भू-अर्जन का मुआवजा दिये जाने के संबंध में गौर मजरूआ सर्वसाधारण का रू० 17,64,047=18 का अवार्ड भूतपूर्व राजा एवं उनके परिवार के सदस्यों के नाम घोषित कर दिया गया, जिसके कारण इतनी बड़ी राशि का अवैध भुगतान हो गया ।

उक्त आरोपों हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-9910, दिनांक 13 सितम्बर, 1996 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री यू० के० संगमा, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन तत्कालीन बिहार में ही दिनांक 27 मई, 1997 को समर्पित किया गया । जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि अवार्ड का प्रस्ताव श्री मिश्र के पूर्वाधिकारी द्वारा सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा गया था । श्री मिश्र के पदस्थापन अवधि के दौरान यह अवार्ड सरकार द्वारा स्वीकृत होकर प्राप्त हुआ। सरकार की स्वीकृति हो जाने के कारण श्री मिश्र द्वारा अवार्ड घोषित कर दिया गया । इस कारण श्री मिश्र ने मात्र सरकार के आदेश का अनुपालन ही किया है, उनके द्वारा कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है । इस कारण संचालन पदाधिकारी द्वारा इन्हें संदेह का लाभ देते हुए इन्हें आरोप मुक्त करने की अनुशंसा की गयी । परन्तु बिहार द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन को स्वीकार नहीं किया गया एवं आयुक्त द०छो० प्रमंडल से कतिपय पृच्छाएँ की गयी ।

विभाग स्तर पर श्री मिश्र के विरुद्ध प्राप्त आरोप एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए संकल्प सं०-5898, दिनांक 7 नवम्बर, 2008 द्वारा इन्हें भविष्य में कोई प्रोन्नति नहीं दिये जाने की सजा दी गयी ।

उक्त संकल्प को निरस्त करने हेतु श्री मिश्र द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका W.P.(S) No. 235/2009 दायर की गयी । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दण्ड संकल्प को निरस्त कर दिया गया, जिसका Operative part निम्नवत् है:-

"At the same time, it appears that the petitioner was facing criminal proceeding in which sanction for prosecution has already been granted by the State. If a sanction for prosecution has been granted for a criminal proceeding or charge sheet has been filed then also the departmental promotion committee ought to keep the matter of promotion of an employee in sealed cover, as per the rules governing the service condition. The petitioner has retired in the meantime and it is informed that criminal proceeding has not concluded, though it is stated that stay was granted on 15.02.2000 in the said case by the Patna High Court. Therefore, though the impugned order on test of legal scrutiny, may not survive, but the petitioner may not be entitled to promotion if a criminal proceeding is still pending

against him and sanction of prosecution in the said criminal proceeding has been granted by the State Government. Therefore, in the facts and circumstances and for the reasons discussed herein-above, the impugned order dated 07.11.2008 cannot be sustained in the eyes of law. Accordingly, it is quashed."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में विधि (न्याय) विभाग से परामर्श प्राप्त की गयी। विधि (न्याय) विभाग द्वारा परामर्श दिया गया कि "भविष्य में कोई प्रोन्नति नहीं दी जाएगी" संबंधी दण्ड के बदले धारा-43(बी) एवं धारा-139(सी) के तहत कार्रवाई किया जाय।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में इनके विरुद्ध दण्ड अधिरोपण से संबंधित संकल्प सं०-5898, दिनांक 7 नवम्बर, 2008 को विभागीय संकल्प संख्या-1111, दिनांक 8 फरवरी, 2016 द्वारा निरस्त किया गया है।

विभाग द्वारा समीक्षोपरान्त, श्री मिश्र के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत इनके पेंशन से 15 (पन्द्रह) प्रतिशत कटौती का दण्ड प्रस्तावित किया गया है, जिसके लिए विभागीय पत्रांक-1316, दिनांक 15 फरवरी, 2016 द्वारा इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री मिश्र के पत्र, दिनांक 27 फरवरी, 2016 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया, जिसमें इनके निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

1. इनका कहना है कि ठोस जानकारी के आधार पर इन्होंने कार्मिक विभाग, बिहार को दिनांक 25 जून, 2001 तथा कार्मिक विभाग, झारखण्ड को दिनांक 15 दिसम्बर, 2004, 24 मई, 2004 तथा 4 मई, 2006 को भेजे गये अपने आवेदन पत्रों में यह निवेदन किया था कि इनके पूर्वाधिकारी द्वारा तैयार एवं बिहार सरकार द्वारा अनुमोदित अवार्ड के आधार पर इन्होंने जनवरी, 1989 ई० में अवार्ड घोषित किया था। लेकिन उसके आधार पर प्रश्नगत भूमि का अवार्ड का भुगतान सक्षम न्यायालय (सिविल कोर्ट) के आदेश के बिना संभव नहीं था और उसे इनके कार्यकाल (22 अगस्त, 1988 से 10 अगस्त, 1989) के बाद उसमें हेरफेर के पश्चात् भुगतान का योग्य बनाकर दिनांक 12 दिसम्बर, 1991 को भुगतान किया गया। कार्मिक विभाग, झारखण्ड को दिनांक 20 अगस्त, 2009 को भेजे गये अपने आवेदन में इन्होंने निवेदन किया था कि इनके द्वारा घोषित अवार्ड में (क) अनावाद सर्वसाधारण (ख) प्रभात कुमार आदित्य देव का नाम था। बाद में भू-अर्जन खतियान में अनावाद सर्वसाधारण को हटाकर प्रताप कुमार आदित्य देव का नाम जोड़ दिया गया।

2. इन्होंने जनवरी, 1989 में ग्राम ईचागढ़ के सैकड़ों अवार्डियों के नाम से तैयार अवार्ड को घोषित किया था। उस समय सिंहभूम जिला का विभाजन नहीं हुआ था। 1990 ई० में सिंहभूम जिला को पूर्वी सिंहभूम के नाम से विभाजित किया गया। इनके द्वारा भू-अर्जन खतियान का अंश संलग्न किया गया है, जिसमें जिला का नाम पश्चिमी सिंहभूम (West Singhbhum) लिखा हुआ है और नीचे इनका हस्ताक्षर दर्शाया गया है, जो असंभव था। इससे स्पष्ट है कि इनके कार्यकाल के बाद इनके जाली हस्ताक्षर से भू-अर्जन खतियान एवं अवार्ड सूची तैयार किये गये और भुगतान किया गया। अगस्त 2009 के पूर्व इस विसंगति की जानकारी इन्हें नहीं थी। इनके पूर्वाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तालाब का पुनर्निर्माण संभव नहीं था। अतः इसमें अनावाद सर्वसाधारण हटाकर प्रभात कुमार आदित्य

देव का नाम जोड़ गया जो तालाब सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है । इसमें दोनों अवार्डियों का नाम एक साथ दर्शाया गया है लेकिन खतियान एवं अवार्ड सूची में अलग-अलग अवार्ड संख्या 478 एवं 479 दर्शाया गया है । इनका यह भी कहना है कि तत्कालीन अंचल अधिकारी, ईचागढ़ में मार्च 1991 ई० में विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी को प्रतिवेदित किया था कि प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान में अनावार सर्वसाधारण के नाम से दर्ज है लेकिन इस पर निर्मित तालाब आवार्डियों के पूर्वजों द्वारा बनाया गया था । इस तालाब को कभी बंदोबस्ती नहीं हुई है । इस प्रकार भुगतान करने वाले पदाधिकारी को यह जानकारी थी कि प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान में अनावार सर्वे साधारण दर्ज है ।

3. जाँच संचालन पदाधिकारी ने गहन जाँच के बाद अपने 27 मई, 1997 के प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया है कि अवार्ड में हस्ताक्षर के समय इनकी गलत मंशा नहीं थी । उन्होंने यह भी लिखा कि इनके कार्यकाल के बाद किये गये दुष्कर्म के लिए इन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए उन्होंने इनके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त करने की अनुशंसा की थी । इनका यह भी कहना है कि प्रथम कारण पृच्छा के संबंधित संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन के 18 वर्षों के बाद तथा इनके सेवानिवृत्ति के 7 वर्ष के पश्चात् इन्हें द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित करने का आदेश न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है । स्पष्ट है कि इन्होंने अनावार सर्वसाधारण की जमीन का व्यक्ति विशेष के नाम से कोई अवार्ड घोषित नहीं किया और इनके कारण सरकार को आर्थिक क्षति नहीं हुई है। इनके अवार्ड घोषित करने के तीन वर्ष के बाद अवार्ड में हेरफेर करने के पश्चात् अवार्डियों को भुगतान किया गया ।

आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप, इनके बचाव-बयान, संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन एवं द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत, श्री मिश्र के विरुद्ध पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत इनके पेंशन से 15 (पन्द्रह) प्रतिशत राशि की कटौती का दण्ड अधिरोपित करने हेतु विभागीय पत्रांक-7773, दिनांक 7 सितम्बर, 2016 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से सहमति की माँग की गई। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-238, दिनांक 25 जनवरी, 2017 द्वारा इनके पेंशन से 15 (पन्द्रह) प्रतिशत राशि की कटौती का दण्ड पर सहमति प्रदान की गयी है ।

अतः श्री मिश्र के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत इनके पेंशन से 15 (पन्द्रह) प्रतिशत राशि की कटौती का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,

सरकार के संयुक्त सचिव ।
